RNI No. 38189/72

पोस्टिंग - प्रति बुधवार

डाक पंजीयन MP/IDC/58/2024-2026

संस्थापक - स्व. श्री जीवन साहू

युग प्रभात

प्रति गुरुवार | साप्ताहिक | राष्ट्रीय समाचार पत्र | हर कदम पर नए युग के साथ

वर्ष - 55, अंक - 13 | इंदौर, 4 से 10 दिसम्बर 2025 | पृष्ठ-8, कीमत 3 रुपए

इंडोनेशिया और श्रीलंका में सैकड़ों लापता

साउथ एशिया में बाढ़ से 1000 की मौत

नई दिल्ली ।

साउथ एशियाई देशों इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड में आए भीषण बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 1,000 से ज्यादा हो गई है। कई देशों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। इंडोनेशिया में मौत का आंकड़ा बढ़कर 502 हो गया है, जबकि 508 लोग अब भी लापता हैं। वहां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने यह अपडेट जारी किया है।

श्रीलंका में कम से कम 340 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी कोलंबो में रातभर पानी बढ़ने के बाद अब बारिश रुक गई है, जिससे उम्मीद है कि पानी कम होना शुरू होगा। श्रीलंका और इंडोनेशिया दोनों ने राहत कार्यों के लिए सेना को तैनात किया है। थाईलैंड के दक्षिणी हिस्सों में आई बाढ़ में 176 लोगों की मौत हुई है। यह पिछले दस वर्षों में वहां की सबसे घातक बाढ़ मानी जा रही है। मलेशिया के उत्तरी पेरलिस राज्य से दो मौतों की जानकारी मिली है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ था साइबर अटैक, विमानों को भटकाने की थी साजिश

● नई दिल्ली।

हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुआ था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सदन को बताया कि हैकर्स ने विमानों के नेविगेशन सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की थी।

मंत्री राम मोहन नायडू ने जानकारी दी कि यह घटना 10 नवंबर को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (आईजीआई) एयरपोर्ट पर घटी थी। उस दिन विमानों के जीपीएस सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की गई थी। तकनीकी भाषा में इसे जीपीएस स्पूफिंग कहा जाता है। इसमें हैकर्स असली जीपीएस सिग्नल की जगह नकली सिग्नल भेजते हैं, जिससे पायलट को विमान की सही लोकेशन और दिशा का पता लगाने में दिक्कत होती है। सरकार के खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। मंत्री ने बताया कि यह हमला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि दिल्ली और कोलकाता समेत देश के कुल 7 हवाई अड्डों पर इस तरह के साइबर अटैक की कोशिश की गई थी। इस दौरान सिस्टम को जाम करने और सिग्नल में गड़बड़ी पैदा करने के प्रयास किए गए।

जीपीएस स्पूफिंग विमान सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है। अगर पायलट गलत सिग्नल को सही मान ले, तो विमान रास्ता भटक सकता है या किसी दूसरी चीज से टकरा सकता है। सरकार ने संसद में यह बात मानकर स्पष्ट कर दिया है कि हवाई सुरक्षा के सामने अब डिजिटल खतरे भी मंडरा रहे हैं। मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि इस चुनौती से निपटने के लिए तकनीकी सुरक्षा घेरे को और मजबूत किया जा रहा है।

बिहार : कांग्रेस के चार विधायक भाजपा के संपर्क में

पटना। बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद गठबंधन के प्रमुख दलों- राजद और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। हार के बाद दोनों दल एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते दिख रहे हैं, जिससे राजनीतिक तनाव और जुबानी जंग बढ़ गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और एलजीपी -रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बिहार में विपक्ष अब पूरी तरह धराशाई हो चुका है और कई विधायक इस डूबती नाव में रुकना नहीं चाहते। भाजपा कुछ भी करके अपना कुनबा बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि नीतिश कुमार पर भाजपा को आज भी भरोसा नहीं है कि वे कब और कैसे पलटी मार जाए।

नवंबर में 1.70 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, अक्टूबर से 26 हजार करोड़ कम

● नई दिल्ली ।

केंद्र सरकार ने सोमवार को नवंबर में हुए जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए हैं। नवंबर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) से 1.70 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। सालाना आधार पर इसमें 0.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

आंकड़ों के मुताबिक, एक साल पहले यानी नवंबर 2024 में सरकार ने 1.69 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किया था। वहीं पिछले महीने अक्टूबर के मुकाबले नवंबर का कलेक्शन 26 हजार करोड़ रुपए घटा है। अक्टूबर में सालाना 4.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1.96 लाख करोड़ रुपए जीएसटी वसूला गया था।

बलूचिस्तान के एफसी हेडक्वार्टर पर हमला, 6 जवानों की मौत

● इस्लामाबाद।

पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के नोकुंदी इलाके में स्थित चगाई में फ्रंटियर कॉर्प्स (एफसी) के मुख्यालय के मेन गेट पर आत्मघाती हमला होने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 6 जवानों की मौत होने की पुष्टि है। यह हमला कथित तौर पर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की सादओ ऑपरेशनल बटालियन द्वारा किया गया। वहीं यह भी जानकारी है कि सभी हमलवरों को भी मारा गिराया गया है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मुख्य द्वार पूरी तरह नष्ट हो गया और पास की दीवारों को भारी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मुख्य प्रवेश द्वार पर हमले के तुरंत बाद हथियारबंद हमलावर नोकुंडी स्थित स्नष्ट मुख्यालय के अंदर घुस गए। मुख्यालय परिसर के भीतर भी हमलावरों और जवानों के बीच झड़प हुई। हमले के मद्देनजर, सभी संबंधित अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दी गई है। घटनास्थल पर सहायता के लिए क्वेटा से 2 हेलीकॉप्टर रवाना किए गए हैं। हालांकि, किसी भी समूह ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

विजय माल्या और नीरव मोदी ही नहीं कई और नाम भगोड़े की लिस्ट में

भगोड़े आर्थिक अपराधियों का राज़ खुला : 15 पर 58,000 करोड़ की देनदारी

● नई दिल्ली।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा को सूचित किया कि 31 अक्टूबर, 2025 तक भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत कुल 15 व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। यह जानकारी संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दौसा से कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीणा द्वारा उठाए गए एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में

मीणा ने लोकसभा में वित्त मंत्री से पूछा कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत आज तक कितने व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर किए गए वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में; इन घोषित भगोड़े आर्थिक अपराधियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हुई कुल वित्तीय हानि (रुपये में) का विवरण, नाम-वार और बैंक-वार; निपटान में शामिल व्यक्तियों का नाम और संख्या, संबंधित बैंकों के नाम, निपटाई गई राशि और दी गई छूट। चौधरी ने कहा कि इन 15 अपराधियों में से नौ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ बड़े पैमाने पर की गई वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल हैं। इस सूची में विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि इन 15 भगोड़े आर्थिक अपराधियों ने सामूहिक रूप से 31 अक्टूबर, 2025 तक बैंकों को 26,645 करोड़ रुपये का मूल वित्तीय नुकसान पहुँचाया है। इसके अलावा, इन ऋणों पर एनपीए बनने की तिथि से 31 अक्टूबर, 2025 तक अर्जित ब्याज 31,437 करोड़ रुपये है।

चौधरी ने सदन को बताया कि 31 अक्टूबर, 2025 तक इन अपराधियों से 19,187 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके हैं। घोषित भगोड़े आर्थिक अपराधियों के नाम हैं- विजय माल्या, नीरव मोदी, नितिन जे संदेसरा, चेतन जे संदेसरा, दीप्ति सी संदेसरा, सुदर्शन वेंकटरमन, रामानुजम शेषरत्नम, पुष्पेश कुमार बैद और हितेश कुमार नरेंद्रभाई पटेल। जब पूछा गया कि भगोड़ों को रोकने के लिए कोई नीति बन रही है तो पंकज चौधरी ने कहा कि वर्तमान में ऐसी कोई नीति तैयार नहीं की जा रही है।

युग प्रभात

संतोष वर्मा बयान विवाद: जयस खुलकर वर्मा के समर्थन में छुट्टी के दिन कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन

इंदौर ।
आईएएस संतोष वर्मा के बयान को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब उनके समर्थन में आदिवासी संगठन 'जय आदिवासी युवा शक्ति खुलकर सामने आ चुका है. संगठन ने आरोप लगाया कि पिछले दिनों अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा द्वारा सामाजिक समरसता पर दिए गए बयान को कुछ लोगों द्वारा तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है, जिसके कारण अनावश्यक विवाद खड़ा किया गया है, इस पूरे मामले में अब जयस संगठन खुलकर संतोष वर्मा के समर्थन में आ चुका है।

जयस राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट लोकेश मुजाल्दा ने कहा कि संतोष वर्मा के बयान की पूरी व्याख्या को गलत दिशा में ले जाया गया है. वर्मा ने किसी भी समाज की बहन-बेटियों का अपमान नहीं किया है. उन्होंने सामाजिक सौहार्द और समरसता की बात करते हुए रोटी-बेटी व्यवहार' का उदाहरण दिया था. उनका स्पष्ट कहना था कि जब तक ऊँची जाति और निम्न जाति के परिवारों के बीच रोटी-बेटी सामाजिक और वैवाहिक) संबंध स्थापित नहीं होते, तब तक आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने की बात करना उचित नहीं है। वर्तमान में जैसा आरक्षण का प्रावधान है, वह जारी रहना चाहिए.एडवोकेट लोकेश मुजाल्दा ने बताया कि संतोष वर्मा जी के समर्थन में ST, SC, OBC और Minority समाज मिलकर चरणबद्ध आंदोलन करेगा।

इसी के तहत रविवार को इंदौर में समाजजन क्रांतिसूर्य टंट्या भील चौराहा से कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च किया और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से निम्न मांगें शामिल है IAS संतोष वर्मा को जारी नोटिस वापस लिया जाए संतोष वर्मा को धमकियाँ देने वालों पर FIR दर्ज की जाए। मध्यप्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरक्षित वर्ग SC,ST,OBC को कुत्ता, गधा, मक्खी, कौवा कहकर अपमानित करने पर एफ़आईआर दर्ज कर जेल भेजा जाए। संविधान व डॉ भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले अनिल मिश्रा पर FIR दर्ज की जाए प्रदेश में सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने की

पत्रकारों पर हमले और सरकारी कार्यालयों में रिश्वतखोरी जोरों पर

इंदौर । समाजसेवी अभिषेक अग्रवाल ने बताया है कि कि मध्यप्रदेश में पत्रकारों पर सरकारी कार्यालय में हमले और निकुंश अधिकारियों के भ्रष्टाचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।गौरतलब हैं की पहले भी रिश्वत खोरी व भ्रष्टाचार की कई खबरें सरकारी कार्यालयों से आती रही हैं। ..आज इंदौर आरटीओ कार्यालय में पत्रकारों के साथ हुई मारपीट निश्चित ही बहुत निंदनीय हैं... चुनी हुई सरकार के विधायक के कर्मचारियों और पुत्र द्वारा हठधर्मिता से ग्रसित होना राज्य की स्थिति को और भी चिंताजनक बना रहा है।आज शाम को विधायक गोलू शुक्ला की गाड़ी के ड्राइवर ने अंधाधुंध बस चलाकर कई लोगों को घायल कर दिया जिसमें से कई गम्भीर हैं ज्ञात हो कि शुक्ला ब्रदर्स की बस से पहले भी कई एक्सीडेंट हो गए जिसमें कईयों की मौत भी हो चुकी हैं। पर सरकार ने कोई कार्यवाही नही की जिससे की आरोपियों के हौसले और भी बुलंद हो गए। प्रदेश के मुखिया का भी इन्हें वरद हस्त प्राप्त है।

यह स्थिति न केवल पत्रकारों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी खतरे की घंटी है। जब पत्रकारों को अपने काम करने के लिए सुरक्षित माहौल नहीं मिलता, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की स्थिति खतरे में पड़ जाती है।

निकुंश अधिकारियों के भ्रष्टाचार और हठधर्मिता से ग्रसित नेताओं के कारण राज्य की विकास यात्रा बाधित हो रही है।

प्रतिबंधित चाइनीज मांझा का बड़ा जखीरा जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार

इंदौर । शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, छत्रीपुरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लगभग 70,000 मूल्य के चाइनीज धागे के 200 रोल जब्त किए हैं। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई डीसीपी आनंद कलादगी और एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल के मार्गदर्शन में, एसीपी हेमंत चौहान और थाना प्रभारी संजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई।

छत्रीपुरा थाना क्षेत्र के रेडियो चौक बियाबानी पर पुलिस टीम ने चैकिंग के दौरान देव ओटकर पिता रमेश ओटकर नामक एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का एक रोल मिला। पूछताछ में देव ने बताया कि वह यह धागा समीर मेव सफीक मेव, निवासी मेवाती मोहल्ला से लाया था।

वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देने के बाद, देव ओटकर द्वारा बताए गए स्थान पर घेराबंदी की गई और आरोपी समीर मेव को उसकी दुकान से भारी मात्रा में चाइनीज धागे के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने समीर मेव की दुकान से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के 200 रोल जब्त किए। जब्त मांझे की अनुमानित कीमत 70 हजार रुपये बताई गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रतिबंधित मांझा मानव जीवन और पशु-पक्षियों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, जिसके चलते इसके उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध है।

गिरफ्तार आरोपियों समीर मेव और देव ओटकर के खिलाफ केस दर्जकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी संजीव श्रीवास्तव के साथ उप-निरीक्षक पवन नरवरे, सहायक उप-निरीक्षक हितेश वाचकर, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र पाठक, माया, अमरपाल, शंशाक, और आरक्षक अरुण सिंह चौहान, रामराज, रामहेत, धर्मेंद्र सिंह सोनगरा, भूपेंद्र सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

विधायक शुक्ला की बसों ने दो माह में 5 की जान ली, पुलिस, आरटीओ चुप

इंदौर ।इंदौर-उज्जैन रोड पर विधायक गोलू शुक्ला के परिवार की बसों ने दो माह में 5 लोगों की जान ली है आरोप है कि पुलिस और आरटीओ की सुस्ती ने बसों के ड्राइवरों के हौसले को बढ़ा दिया है। परिवार ने कार्रवाई की अपील की है, लेकिन अधिकारी मौन हैं इंदौर-उज्जैन के बीच चल रही बस से हुए एक्सीडेंट में अब महिला की भी मौत हो गई है। यह बस विधायक गोलू शुक्ला के परिवार की बाणेश्वरी ट्रैवल्स (शुक्ला ब्रदर्स) की है शुक्रवार को इंदौर-सांवेर रोड पर धरमपुरी के पास हुए एक्सीडेंट में दो बाइक पर सवार चार घायल हुए थे।

इनमें शामिल महिला की मौत हो गई है।इंदौर पुलिस और आरटीओ की सुस्ती का असर यह है कि बाणेशवरी ट्रैवल्स के ड्राइवर मद-मस्त हैं नियम-कायदों को ठेंगा दिखाकर बेखौफ बसें दौड़ा रहे हैं। इनकी हुई मौत घटना में कलाबाई पति आजम उम्र 48 साल, आजम पिता अकरम उम्र 50 साल, दोनों निवासी नरवल थाना बाणगंगा इंदौर के थे। सारांश यादव उम्र 13 व शिवांग यादव उम्र 20 साल दोनों हेमंत यादव के बेटे हैं। ये इंदौर के हाईवे ड्रीम सिटी के निवासी हैं। उपचार के दौरान कलाबाई की मौत हो गई।परिवार बोला विधायक ड्राइवरों को समझाएं उधर कलाबाई के परिजनों ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने विधायक गोलू शुक्ला से अपील की कि वे ड्राइवरों को समझाएं।

वे चाहते हैं कि ड्राइवर बस चलाते वक्त सावधानी बरतें और तेज रफ्तार से न दौड़ाएं आरटीओ से भी निवेदन किया गया कि बसों की स्पीड तय करें और कार्रवाई करें। पहले जब पूरा परिवार खत्म हुआ था, विधायक ने कहा था कि वे इस हादसे से दुखी हैं। वे ड्राइवरों को समझा रहे हैं कि बसें सावधानी से चलाएं।विधायक गोलू शुक्ला जुड़ी खबर पर एक नजर 28 नवंबर को इंदौर-सांवेर रोड पर धरमपुरी के पास बाणेशवरी ट्रैवल्स की बस से हुई दुर्घटना में चार लोग घायल हुए, जिनमें महिला कलाबाई की उपचार के दौरान मौत हो गई।कलाबाई के परिजनों ने विधायक गोलू शुक्ला से अपील की है कि वे ड्राइवरों को सावधानी से बस चलाने के लिए समझाएं और तेज रफ्तार से बचने की सलाह दें। दो महीने में बाणेशवरी ट्रैवल्स की बसों से पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक परिवार की पूरी तरह से मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इन हादसों के खिलाफ सामान्य धाराओं में ही केस दर्ज किया है, और आरटीओ ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे ड्राइवरों का हौसला बढ़ा है 28 नवंबर को दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बस को घेरकर ड्राइवर और कंडक्टर को पीटा और बस की रफ्तार को लेकर आक्रोश व्यक्त किया इस तरह 5 को लील गई गोलू की बसें। इन बसों पर आगे शुक्ला ब्रदर्स और पीछे गोलू लिखा होता है। इन बसों से दो माह में 5 की मौत हो गई।17 सितंबर को शुक्ला ब्रदर्स की बस ने रिंगनोदिया के पास बाइक को टक्कर मारी थी। इसमें पूरा परिवार चार लोगों की मौत हो गई थी। इसमें महेंद्र सोलंकी, पत्नी जयश्री व बेटे जिगर व तेजस का निधन हुआ था।

दोस्ती के जाल में फंसाकर डेढ़ साल तक दरिंदगी और ब्लैकमेल

फर्जी नामों से किया शोषण, धर्म परिवर्तन का दबाव और लाखों की वसूली

इंदौर ।शहर में एक युवती को दो युवकों ने पहले दोस्ती के बहाने फंसाया, फिर अश्लील वीडियो और धमकियों के दम पर डेढ़ साल से अधिक समय तक लगातार शारीरिक और मानसिक शोषण किया। आरोपियों ने युवती से लाखों रुपये वसूले, उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और जान से मारने की धमकियां दीं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महालक्ष्मी नगर इलाके में किराए से रहने वाली और प्राइवेट नौकरी करने वाली पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2021 में एक कैफे में उसकी दोस्ती %मोहित% नाम के युवक से हुई थी। शिकायत के अनुसार, 6 मार्च 2022 को मोहित उसके फ्लैट पर पहुंचा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने विरोध किया, तो उसने मोबाइल में मौजूद फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

बाद में युवती को पता चला कि मोहित का असली नाम सुफियान इरशाद अंसारी है। पीड़िता ने बताया कि सुफियान ब्लैकमेल कर लगातार संबंध बनाता रहा और उससे करीब पाँच लाख रुपए वसूल चुका है। साथ ही, उसने कई खर्चे भी युवती से कराए।

दूसरे आरोपी ने भी किया ब्लैकमेल

पीड़िता ने बताया कि सुफियान के एक दोस्त अमर से भी उसकी बातचीत होती थी, जिसका वास्तविक नाम अमीर उर्फ गोल्डन है। जब पीड़िता ने सुफियान से बात करना बंद किया, तो अमीर ने उससे मिलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

फर्जी डीएड सार्टिफिकेट से नौकरी पाने का मामला

मार्कशीट के वेरिफिकेशन को लेकर भी उठे सवाल

भोपाल । शिक्षा विभाग में फर्जी डीएड अंकसूची से नौकरी पाने के मामले में मप्र स्पेशल टॉस्क फोर्स (एमपी एसटीएफ) ने प्रदेश के कई जिलों में फर्जी डीएड सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला दर्ज होने के बाद आगे की जॉच में अब डीएड अंकसूची के सत्यापन को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल में लगभग सभी कार्य हाईटेक होने के बाद भी डीएड अंकसूची के सत्यापन को ऑफलाइन ही रखा है। बताया गया है की दसवीं-बारहवीं की मार्कशीट और आंसर शीट की चैकिंग तक का काम ऑनलाइन कर दिया गया है। वहीं परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने वाले हाईटेक माशिमं में सिर्फ डीएड की अंकसूचियों के सत्यापन का कार्य ऑफलाइन चल रहा है। सूत्रों के अनुसार इस संबध में एसटीएफ द्वारा विभाग से दस्तावेज मांगे गए हैं। और जिन जिलो के ऐसे अधिकारी जो वर्तमान में लोक शिक्षण में पदस्थ हैं, उनसे आगे की जॉच के दौरान पूछताछ की जा सकती है। गौरतलब है कि फर्जी डिग्री से सरकारी शिक्षक की नौकरी पाने के सबसे अधिक मामले मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, इंदौर समेत अन्य जिलों में हैं। एसटीएफ जांच में सामने आया है की साल 1998 से 2006 तक जिला और जनपद पंचायत के माध्यम से डीएड की फर्जी अंकसूची का खेल चला है। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संभाग या जिला स्तर पर बनाई नियोक्ता कमेटी द्वारा डीएड की फर्जी अंकसूची का सत्यापन कर मार्कशीट की रिपोर्ट को सही किया गया। ग्वालियर ईकाई एसपी, एसटीएफ अधिकारियो का कहना है कि फिलहाल माशिमं को लेकर किसी तरह की गड़बडी की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि इस मामले से संबंधित जिलों के कुछ अधिकारी वर्तमान में लोक शिक्षण में पदस्थ हैं। आग की जांच जारी है, और पड़ताल के दौरान आरोपियो की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल जॉच टीम यह पता लगा रही है की नौकरी पाने वाले उम्मीदवारो की फर्जी डिग्री का सत्यापन कर उसे सही बताने वाले आरोपी कौन है, और फर्जीवाड़े में जिसकी भी मिलीभगत सामने आयेगी उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश में उत्तम शिक्षा एवं कौशल विकास के केन्द्र बन रहे हैं सांदीपनि विद्यालयः मुख्यमंत्री

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति वर्ष 2020 के अनुरूप स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिये राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश के सांदीपनि विद्यालयों ने अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिये जाने के साथ ही उनके कौशल विकास और उन्हें रोजगार से जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य में सांदीपनि विद्यालय की शुरूआत वर्ष 2022-23 शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ हुई। इस सत्र में प्रथम चरण में प्रदेश में 274 सांदीपनि विद्यालय शुरू किये गये। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 3 लाख से ऊपर हो गयी है। विद्यालय में केजी-वन से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 88 प्रतिशत और कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 84 प्रतिशत तक रहा है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने सांदीपनि विद्यालयों में अधोसंरचना के विस्तार को प्राथमिकता दी है। राज्य में 256 सांदीपनि विद्यालय भवनों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। विद्यालयों के भवन निर्माण एवं संसाधनों की सुविधा के लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने लगभग 10 हजार करोड़ रूपये की कार्ययोजना तैयार की है। अब तक 44 सांदीपनि विद्यालयों के नवीन भवन बनकर तैयार हो गये हैं। इन नवीन भवनों में सांदीपनि विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। अगले शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 में 256 विद्यालयों का भवन निर्माण पूरा कर लिया जायेगा। सांदीपनि विद्यालयों में निकटस्थ 10 से 15 किलोमीटर दूरी के विद्यार्थियों को लाने के लिये निःशुल्क परिवहन सेवा भी प्रदान की जा रही है।

प्रदेश में संचालित सभी सांदीपनि विद्यालयों में पूर्णतः सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर लेब, आर्ट एण्ड क्राफ्ट रूम, म्यूजिक रूम, आधुनिक लाइब्रेरी और खेल मैदान के साथ ऑडिटोरियम की सुविधा भी दी गई है।

खाना खाकर सोये पति ने रात को लगा ली फांसी

भोपाल । शहर के पिपलानी थाना इलाके में बीती रात एक व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर कारणो की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 60 क्वार्टर झुग्गी बस्ती में रहने वाला सौरभ रघुवंशी पिता सुमेश रघुवंशी (30) मेंहनत-मजदूरी का काम करता था। उसकी पत्नी रेश्मा कुंडे ने पुलिस को बताया की वह बंगलो में साफ सफाई का काम करने जाती है, उसका एक पॉच साल का बच्चा भी है। परिवार में उसके साथ ही उसकी की बहन भी रहती है। पति सौरभ को शराब पीने की लत थी, बीती रात भी सौरभ शराब के नशे में घर आया और खाना खाकर कमरे में सोने चला गया। परिवार वालो की नींद खुली तो उन्हें सौरभ का शरीर फांसी के फंदे पर लटका नजर आया।

हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा

जनहित याचिका पर नोटिस जारी, अगली सुनवाई 13 जनवरी 20 26 को

इंदौर ।
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए मप्र हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के पालन की मांग की गई है। सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है और याचिका की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होगी। इन्दौर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट , इंदौर खंडपीठ में दिग्विजय सिंह की जनहित याचिका पर नोटिस हुए हैं। पूर्व सीएम सिंह ने सांप्रदायिक हिंसा रोकने वाली सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन लागू करने की मांग की। उन्होंने धार्मिक रैली और जुलूसों पर जारी दिशा-निर्देशों के पालन की बात कही है।

हाई कोर्ट में 27 नवंबर को इस महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी हुई थी। खास बात यह है कि सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह ने स्वयं अपनी पैरवी की थी। हाईकोर्ट ने यह दिए आदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन से इस मामले में जवाब मांगा है। शासन से याचिका में उठाए मुद्दों के पालन नहीं होने को लेकर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।

इस मामले में अब अगली सुनवाई13 जनवरी 2026 में रखी गई है। याचिका के दौरान दिग्गी को बताया था अपराधी याचिका की सुनवाई के दौरान शासन पक्ष ने सिंह पर 11 एफआईआर होने की बात कहते हुए उन्हें अपराधी बताया था। साथ ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हो रहा है इसलिए याचिका का कोई मतलब नहीं है। इस

सिंह ने रखे अपने तर्क

हालांकि सिंह ने ही अपने तर्क रखे यह बोले थे दिग्विजय सिंह हाईकोर्ट डबल बैंच के सामने सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। लेकिन उपद्रव होने, धार्मिक रैली, जुलूस को लेकर इनका पालन नहीं हो रहा है। पीड़ितों को कैसे मुआवजा मिलेगा, जिले में किस पुलिस अधिकारी से संपर्क करे, यह सब नहीं हो रहा है। मस्जिदों के बाहर जाकर लाउडस्पीकर बजाए जाते हैं, डीजे बजाए जाते हैं। पुलिस, प्रशासन मूकदर्शक बना रहता है। किसी पर कार्रवाई नहीं होती है। शासन की ओर से यह कहा गया-शासन की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। साथ ही इस मामले में जो मामले याचिका में बताए गए हैं, इसमें जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की गई है।

स्टेटस रिपोर्ट जारी करे

इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसा है तो शासन इस पर स्टेटस रिपोर्ट जारी करे। इस संबंध में कहीं कोई जानकारी नहीं है। या फिर न्यायमित्र नियुक्त पर सिंह ने कहा था कि मुझे तो शासन ने आदतन अपराधी बता दिया। जबकि मुझ पर राजनीतिक केस है, कोई भ्रष्टाचार या इस तरह का केस नहीं है। मैं 55 साल से जनसेवा में हूं, इसलिए इस तरह के केस तो राजनीतिक होते हैं सुनवाई होते ही लाइव स्ट्रिमिंग कराई थी बंद याचिका की सुनवाई 27 नवंबर को दोपहर करीब 1 बजे शुरू हुई।

इसी दौरान अधिवक्ता ने लाइव स्ट्रिमिंग का अन्य उपयोग की बात कहते हुए इसे बंद कराने का आग्रह किया। इसके बाद बंद कर दिया गया था। सिंह की याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र सिंह छाबड़ा और अधिवक्ता अमन अरोरा है।

किया जाए। सभी पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामला हियर्ड एंड रिजर्व में रख लिया था, जो अब जारी हो गया है। याचिका में इन सभी को बनाया गया पक्षकार पूर्व सीएम सिंह ने इस मामले में याचिका लगाई हुई है जिसमें मप्र शासन, पीएस गृह विभाग, डीजीपी के साथ ही इंदौर, उज्जैन, मंदसौर कलेक्टर व एसपी को पक्षकार बनाया है।

दिग्गी ने राममंदिर को लेकर यह कहा है याचिका में सिंह ने याचिका में इंदौर, उज्जैन, मंदसौर में दिसंबर 2020 के दौरान हुई घटनाओं के उदाहरण दिए। उन्होंने एफआईआर आदि के साथ गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंह ने कहा है कि श्रीराम मंदिर के पवित्र निर्माण काम के दौरान दान संग्रह किया गया। इस दौरान कुछ संगठनों द्वारा इंदौर, उज्जैन व मंदसौर में साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई।इससे शांति सद्भाव खत्म हुआ और संपत्तियों का नुकसान हुआ। सिंह ने् कहा कि हम राम मंदिर निर्माण के पवित्र काम का समर्थन करते हैं। लेकिन फंड कलेक्शन स्वैच्छिक होना चाहिए दान देने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग पर दबाव नहीं हो और ना ही धमकाना चाहिए।दान देने की आड़ में कुछ संगठनों ने अल्पसंख्यक वर्ग को टारगेट किया। धन संग्रह रैलियों के दौरान आयोजकों द्वारा सुनियोजित तरीके से हिंसा फैलाने का काम किया। लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों ने लापरवाही बरती और कोई कारवाई नही की।

इस मामले में शासन को भी रिप्रेजेंटेश दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए याचिका दायर की है।पूर्व सीएम की माब लिंचिंग रोकने की मांग पूर्व सीएम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के तीन फैसलों को मप्र में लागू करने की मांग की। खासकर माब लिंचिंग और माब वायलेंस रोकने के लिए सख्त कदम उठाना ज़रूरी है।धार्मिक रैलियों व जुलूसों में शांति-सद्भाव बनाए रखने के लिए उपाय करने चाहिए। इसके लिए हर जिले में नोडल पुलिस अधिकारी और एक टास्क फोर्स हो। यह फोर्स इंटेलिजेंस, हेट स्पीच पर नजर रखकर पूरी तरह से नियंत्रण करे।इंदौर के इस विवाद का उदाहरण दिया इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका में सिंह ने 29 दिसंबर 2020 के इंदौर, चंदनखेड़ी विवाद का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि मनोज चौधरी के नेतृत्व में लोग तलवार-स्टिक लेकर निकले थे। वहां अल्पसंख्यकों पर हमले हुए थे, पर पुलिस व प्रशासन ने कुछ नहीं किया था।

मेट्रो, निर्माण गुणवत्ता को लेकर स्पाट निरीक्षण

इंदौर । मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक एस. कृष्ण चैतन्य द्वारा इंदौर मेट्रो परियोजना एवं गांधी नगर डिपो क्षेत्र का दो दिवसीय निरीक्षण 28 एवं 29 नवम्बर 2025 को किया गया। इस निरीक्षण का उद्देश्य परियोजना के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्ध प्रगति तथा आगामी संचालन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करना रहा। गत 28 नवम्बर को शाम 4 बजे गांधी नगर स्थित इंदौर मेट्रो कार्यालय में विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं कॉन्ट्रैक्टर्स उपस्थित रहे। बैठक में अंडरग्राउंड मेट्रो रूट की प्रगति, तकनीकी तैयारियों एवं निर्माण कार्यों की चरणवार स्थिति पर गहन चर्चा हुई। बैठक के दौरान प्रबंध संचालक ने सभी अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया कि शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए, ताकि इंदौर की जनता को सुरक्षित, समयबद्ध, पर्यावरण-अनुकूल और विश्वस्तरीय शहरी परिवहन सुविधा समय पर उपलब्ध कराई जा सके। प्रबंध संचालक द्वारा आज प्राथमिकता कॉरिडोर पर विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मालवीय नगर चौराहा स्टेशन से सुपर कॉरिडोर-2 स्टेशन तक लगभग 11 किमी लंबा ट्रॉली ट्रायल संचालित किया गया, जिसमें कार्यों की वास्तविक प्रगति का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रबंध संचालक ने निम्न स्टेशनों का दौरा किया-विजय नगर, मेघदूत गार्डन, बापट चौराहा, हीरानगर, चंद्रगुप्त चौराहा एवं मालवीय नगर चौराहा।

सम्पादकीय

एसआईआर के मकडजाल, किसी को नहीं मिल रहा निकलने का रास्ता

केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर का जो मकडजाल बुना गया है। इस मकडजाल में फंसकर अब चुनाव आयोग भी फड़फड़ा रहा है, लेकिन उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे भी नहीं मिल रहा है। विपक्षी दल एसआईआर की मार से कराह रहे हैं उन्हें भी इस एसआईआर के मकडजाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 5 महीने से एसआईआर को लेकर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के महान न्यायाधीशों को भी समझ में नहीं आ रहा है। इस एसआईआर के मकडजाल से वह कैसे बाहर निकलें। खंडपीठ के न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए। इसके बाद भी एसआईआर की सुनवाई खत्म नहीं हुई, ना ही कोई अंतिम फैसला सुप्रीमकोर्ट इतने महीने के बाद भी कोई रास्ता निकाल पा रही है। कई राज्य सरकारों ने अलग-अलग पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रखी हैं। देश के महान अधिवक्ता इस मामले में लगातार अपनी दलीलें रख रहे हैं। तारीख पर तारीख के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं लग पा रहा है। एसआईआर की जब सुनवाई शुरू हुई थी, उस समय बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कई महीने बाकी थे। चुनाव आयोग ने वहां चुनाव भी करा दिया, लेकिन जिस विवाद को लेकर विपक्ष और स्वयंसेवी संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, वह आज भी नतीजे को लेकर अपना हाथ मल रहे हैं। चुनाव आयोग की जादूगरी और दूरदर्शिता को लेकर सभी विपक्षी दल हैरान और परेशान है। एसआईआर बाद में शुरू होती है, चुनाव आयोग पहले ही संभावना व्यक्त कर देता है, कि इतने लाख वोट इस राज्य में कटेंगे। चुनाव आयोग जो कहता है, और जो करना चाहता है, वह कर पाता है। सुप्रीम कोर्ट हर बार सुनवाई करने के बाद यह कहती है, यदि कोई गड़बड़ी होगी तो वह एसआईआर को निरस्त कर देंगे। इसी बीच बिहार राज्य के चुनाव संपन्न हो गए। चुनाव परिणाम आ गये,वहां पर एनडीए गठबंधन की सरकार भी बन गई। भाजपा ने जो दावे किए थे। उससे ज्यादा सीटें उन्हें बिहार में मिल गई हैं। अब 12 राज्यों में एसआईआर चल रही है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से 12 राज्यों के मतदाताओं का जीवन दूभर हो गया है। मतदाता 2003 की मतदाता सूची में अपने जिंदा और मरे हुए पूर्वजों और रिश्तेदारों को खोज रहे हैं। कहीं कुछ मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ रिश्तो को चुनाव आयोग मानता नहीं है। रही सही कसर बीएलओ और असिस्टेंट बीएलओ पूरी कर रहे हैं। जितने कम समय में सघन परीक्षण करवाया जा रहा है। वह उतने कम समय में संभव ही नहीं है। चुनाव आयोग हथेली में दही जमाना चाहता है, या दही के बहाने कुछ और जमाना चाहता है। इसको लेकर तरह-तरह की बातें सामने आने लगी हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के दतिया में भारतीय जनता पार्टी और संघ के पदाधिकारियों को दतिया के निर्वाचन अधिकारी ने असिस्टेंट बीएलओ बनाकर उन्हें मतदाता सूची के काम में लगा दिया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस तरह की नियुक्ति पर आपत्ति जताई, जांच कराई गई तो जीतू पटवारी के आरोप सही पाए गए। उसके बाद दतिया कलेक्टर ने माफी मांगते हुए चुनाव अधिकारी को निलंबित किया। जो असिस्टेंट बीएलओ बनाए गए थे उनकी नियुक्तियां निरस्त की गई। एसआईआर को लेकर अन्य राज्यों में नये -नये कारनामे उजागर हो रहे हैं। बिहार के बीएलओ ने बिना मतदाता के घर जाए मनमाने तरीके से जिसके वोट बनाने थे, उनके बना दिए। लगभग 62 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काट दिये। जिनके नाम कटे, उनमे अधिकांश मुस्लिम और गरीब थे। जिनके नाम अंतिम समय जोड़े गए।

आज के दौर में इनोवेशन के लिए साइंस कम्युनिकेशन सबसे ज़रूरी

आज देश को विज्ञान की सही जानकारी हेतु विज्ञान संचार बहुत जरुरी है, यदि आप बेरोजगार हैं, तो इन वास्तविकताओं का सामना करने से आप अक्सर अभिभूत, उदास और निराश महसूस कर सकते हैं। वैश्विक महामारी के लिए ये वैध प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन इनोवेशन के लिए साइंस कम्युनिकेशन या विज्ञान संचार सबसे ज़रूरी है सकारात्मक बने रहेगें विज्ञान संचार को हम यूं समझ सकते है, जैसे कि वैज्ञानिक जानकारियों जहां से पैदा हो रही हैं। वहां से लेकर उन जानकारियों के प्रयोग करने वालों तक पहुंचाना। इसके लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम अपनाए जाते हैं। विज्ञान संचार को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला शोधपरक विज्ञान संचार और दूसरा लोकप्रिय विज्ञान संचार। लैब में होने वाले शोधों की जानकारी तकनीकी भाषा में होती है। इसे आम आदमी सुगमता से नहीं समझ सकता। लोकप्रिय विज्ञान संचार में यह परेशानी आती है कि विज्ञान की कठिन बातों को सरल कैसे बनाया जाए और आम लोगों तक पहुंचाया जाए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि रिसर्च पेपर की भाषा को आम लोग समझ नहीं पाते और वैज्ञानिक आम जन की भाषा को नहीं समझ पाते। यहीं पर परेशानियां पैदा होती हैं।

वास्तव में विज्ञान के जटिल तर्कों को सरल भाषा में जो भी आम लोगों तक पहुंचा देगा वही एक सफल विज्ञान संचारक कहलाएगा। वास्तव में विज्ञान संचार के दो प्रमुख उद्देश्य हैं-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी आम जन तक पहुंचाना और उनमें वैज्ञानिक-तकनीकी दृष्टिकोण का विकास करना। किसी भी व्यक्ति में जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित होने की बात की जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि उसमें सोच, आचरण, व्यवहार और निर्णय लेने के स्तरों पर वैज्ञानिकता की छाप अवश्य दिखे।इसी छाप को अखिल भारतीय स्तर पर बनाये रखने के लिए हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद, मुंबई द्वारा पिछले 57 वर्ष से लगातार विज्ञान संचार किया जा रहा जिसमें किसी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष श्री आर के मिश्र का हिंदी विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनके हिंदी विज्ञान में एक नई क्रांति मुंबई के वैज्ञानिकों ने 1968 में भारतीय वैज्ञानिक द्वारा हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद की नींव मुंबई में रखी और 2साल बाद वैज्ञानिक पत्रिका का सतत प्रकाशन हुआ जो आज भी ऑनलाइन माध्यम से चल रही है। अतः राष्ट्रीय अस्तर पर हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद ही एक मात्र ऐसी संस्था बची इसमें परिषद के पूर्व कार्यकारी सचिव श्री राजेश कुमार मिश्र का सबसे अधिक और अहम् योगदान रहा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष राजेश कुमार मिश्र , दिनांक 30. 11.2025 मे केंद्र से सेवानिवृत्त हो रहे हैं ।

फिलहाल वे परिषद द्वारा प्रकाशित होने वाली राष्ट्रीय पत्रिका के संपादक मंडल मे हैं इसके पूर्व उन्होंने जून 2022 से सितम्बर 2025 तक वैज्ञानिक पत्रिका के मुख्य संपादक के रूप में सफलतापूर्ण कार्य किया।उनके कार्यकाल में जो अंक प्रकाशित हुए उसमें आजादी के अमृत महोत्सव पर देश में विज्ञान का 75 साल में विकास, टेक्नोलॉजी विशेष अंक, वैज्ञानिक अनुक्रम विशेष,विज्ञान संचार विशेष, महान वैज्ञानिक योगदान अंक, व हाल ही में महान वैज्ञानिक परमाणु वैज्ञानिक डॉ आर चिदंबरम जो पूर्व में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे जिनका 1998 में भारत के पोखरण -2 में मुख्य भूमिका रही उनके निधन पर श्रद्धांजलि के रूप में डॉ आर चिदंबरम स्मृति अंक वैज्ञानिकों व विज्ञान पाठकों के लिए बहुत ही शानदार रहा जिसके लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव महोदय ने अंक हेतु अपनी शुभकामना संदेश देकर वैज्ञानिक में नई संजीवनी दि, जो विज्ञान के प्रकाश से जगमगाते रहे।

राजेश कुमार मिश्रजी ने विज्ञान संचार हेतु वैज्ञानिक को नवाचार और देश के विज्ञान गतिविधियों को पत्रिका में स्थान देकर देश को विज्ञान संचार के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है और लगातार अपनी सेवा निस्वार्थ भाव से देते आ रहें है।इसके पहले वे वह हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद में लगभग 18 सालों या उससे अधिक समय से सक्रिय रूप से जुड़े रहे इसके लिए उन्होंने परिषद द्वारा आयोजित कई राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी में संयोजक के रूप मे महत्वपूर्ण योगदान दिया व हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद द्वारा आयोजित प्रश्न मंच कार्यक्रम मे भी संयोजन मे सफलतापूर्वक काम किया हिंदी विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान हेतु परिषद द्वारा उन्हे हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद स्वर्ण जयंती समारोह, में भारत के महान वैज्ञानिक स्व डॉ चिदंबरम जैसे महान वैज्ञानिक को मंच पर मुख्य अथिति के रूप में बुलाये जाने का पूरा श्रेय जाता है।इसके अलावा वे विज्ञान वार्ता, स्वास्थ्य संगोष्ठी, वैज्ञानिक पत्रिका के व्यवस्थापण मे भी मुख्य भूमिका प्रदान किया गया. उन्होंने विज्ञान अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी, दोनों ही क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

एक प्रभावी विज्ञान संचारक के नाते जन सामान्य संबंधित विषयों की वैज्ञानिक जानकारी/ज्ञान के संचार तथा लोकप्रियकरण की दिशा में स्वयंसेवी भाव से लगातार कार्य करते रहे हैं और वैज्ञानिक पत्रिका मे संपादक मंडल मे बने रहेंगे। सेवानिवृत्ती के अवसर पर आपको हिंदी विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान हेतु अनेक बधाइयां तथा भविष्य के सुखद एवं निरोगी सुदीर्घ पारिवारिक जीवन के लिए शुभकामनाएं !.हिंदी विज्ञान में उनके अहम् योगदान हेतु पूरा देश गौरव महसूस करेगा हिंदी विज्ञान के लिए किया गया उनका कार्य निश्चित रूप से सभी को प्रेरणा देगी । निश्चित तौर पर विज्ञान संचारकों के लिए वैज्ञानिकता का प्रचार प्रसार करना एक बड़ीचुनौती है। विज्ञान संचार के लिए खोजे गए सूत्रों और तत्वों के आधार पर बहुत कुछ किया जा सकता है। नए पीढ़ी के लोगों के लिए चुनौतियां काफी हैं। यह भी साफ है कि केवल विज्ञान की जानकारी रखने वाले लोग ही अच्छे विज्ञान संचारक नहीं होते बल्कि जिनमें वैज्ञानिक समझ विकसित हो जाती है ,अतः विज्ञान संचार बहुत जरुरी है ।

गिद्ध और मांस की पोटली की आधुनिक कथा...

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को बैठाकर निर्देश दिया है कि बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करें। गृहमंत्री सम्राट चौधरी लोगों को चेता रहे हैं कि अब अपराधियों की खैर नहीं। बीस वर्षों से जदयू - बीजेपी का शासन है। अब तक न तो बिहार भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, न अपराधी मुक्त। पता नहीं और कितना वक्त लगे ? शायद जन्म जन्मांतर तक। आज राजनीति की जो दशा है, उसमें कोई भी समाज न भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है, न अपराधी मुक्त। आज की राजनीति ही भ्रष्टाचार और अपराध की जननी है। उसमें रचे बसे लोग अगर दावा करें कि वे समाज को भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त कर देंगे, तो हंसने के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। बीस वर्ष मुख्यमंत्री बने रहने के बाद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करो तो अभी तक वे क्या कर रहे थे ? दिल्ली के पांचवें दशरथ - पुत्र ने तो कहा है कि भारत को विकसित करने के लिए 2047 तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक उनका डेरा - डंडा उठ चुका होगा , तब फिर कोई छठा पुत्र आयेगा जो भारत को 2075 तक विकास करेगा। झूठ और ढकोसले इस युग की खासियत है। कभी विष्णु अवतार, कभी नान बायोलॉजिकल, तभी कभी कुछ। एक प्रवक्ता है, टेलिविजन पर मुंह उठाए आते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे कृष्ण के जन्म के समय झमाझम बारिश हो रही थी, वैसी ही बारिश आधुनिक विष्णु के जन्म के समय हुई थी। इसलिए बेहतर होगा कि राम मंदिर के ध्वजारोहण के समय उनका भी भव्य मंदिर बना दिया जाय। गजब गजब नमूनों का जन्म इस देश में हो गया है। असत्य तो उसके मुंह से ऐसे निकलता है जैसे खपड़ी में चना फूटता है। पहले भी जो राजा गद्दी पर बैठता था, वह अपने को ईश्वर का अवतार ही मानता था।

खैर, मैं तो बिहार के बारे में बात कर रहा था। जब तक चुनाव में भ्रष्टाचार है, वोटरों की खरीद फरोख्त है, सरकारी स्तर पर फिजूलखर्ची है, अफसरों की लूट-खसोट है -तब तक भ्रष्टाचार पर लगाम संभव नहीं दिखता। भ्रष्टाचार की गंगोत्री दिल्ली - पटना में है। गांव घरों को तो अपनी भ्रष्टाचार - सिद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमाम में नंगे लोग अगर सबको कपड़े पहनने का आह्वान करे तो उसकी बात कोई क्यों मानेगा ? जिसके हाथ अनंत सिंह जैसे अपराधी को टिकट देने से नहीं कांपे और हत्यारोपी विधायक बनाता रहे, उसके राज में अपराध खत्म कैसे होगा ?

गिद्ध को मांस की पोटली थमा दी जाय और आप यह खुशफहमी पाल लें कि मांस सुरक्षित रहेगा, तब ऐसी खुशफहमी के बारे में क्या कहा जाए ? चुनाव के पहले हमारे कुछ साथी भ्रम पाले हुए थे कि इस चुनाव के देश में नवजागरण आ जायेगा। बिहार क्रांतिकारियों की धरती है और उसकी धरती में बहुत बल और ऊर्जा है , वहां से लोकतंत्र के नये गीत लिखे जायेंगे। यह भ्रम उम्मीद है टूट चुका होगा। अगर चुनाव में लूटपाट हुई तो कम से कम एक दिन तो बिहार बंद रहना चाहिए था। मगर राजनीति के धुरंधर फिर चुनाव की प्रतीक्षा में लग गए।<

लोकतंत्र पर आये संकट को चिह्नित कर जब तक समाधान और संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाया जायेगा, तब तक कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। देश में क्रोनी कैप्टलिज्म सिर पर चढ़ कर बोल रहा है। इसकी मुकम्मल समझ की जरूरत है। वरना बीमारी जड़ में है, लेकिन इलाज पत्ते और डालियों का करते रहेंगे। सत्ता में कायम रहने के लिए नये नये नैरेटिव गढ़े जायेंगे और देश ? उसके शिकार होता रहेगा।

युग प्रभात

भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आईएफएम की कड़ी चेतावनी

भारत की अर्थव्यवस्था पिछले एक दशक में दुनिया की तेज़ी से उभरती हुई शक्तियों में शामिल रही है। हाल ही में जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (आईएफएम) ने भारत की मुद्रा स्थिति को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है, वह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंताजनक संकेत हैं। आईएफएम ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है, भारतीय रुपया जल्द ही 'अस्थिर मुद्राओं की सूची' में शामिल किया जा सकता है। यह स्थिति भारत की अर्थव्यवस्था और अर्थ प्रबंधन पर घंभीर सवाल उठाता है। भारत सरकार के आर्थिक नीति-निर्माताओं के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। रुपये की कमजोरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसकी गिरावट लगातार तेज़ हो रही है। वैश्विक बाज़ार में डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की बढ़ती क़ीमतें और विदेशी निवेश का भारत से पलायन यह तीनों ऐसे कारण हैं जो रुपये पर भारी दबाव डाल रहे हैं। बाहरी कारणों के साथ-साथ घरेलू बाजारों मे भी चुनौतियाँ लगातार बढ़ रही हैं। बढ़ती महंगाई, नौकरी में छटनी और नई नौकरी नहीं मिलना, रोजगार के अवसरों में ठहराव, औद्योगिक उत्पादन में कमी से आर्थिक असंतुलन बुरी तरह से गड़बड़ाता जा रहा है। आईएफएम की चेतावनी का सबसे अहम कारण जिस तरह से डॉलर की खरीद और बिक्री करके रिजर्व बैंक और अन्य कारोबारी, रुपए की स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, आईएफएम ने इसको सबसे ज्यादा

चिंताजनक माना है। यदि आईएफएम ने रुपया को अस्थिर मुद्रा की श्रेणी में डाल दिया, तो इसका सीधा असर आम भारतीय और भारतीय अर्थ व्यवस्था पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। आयात महंगा होगा, पेट्रोल-डीजल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक की कीमतें उसी हिसाब से बढ़ेंगी। महंगाई तेजी के साथ बढ़ेगी। सरकार, कारोबारी और आम जनता के सामने आर्थिक मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। यह स्थिति निवेशकों के विश्वास को शेयर बाजार से हटा सकती है, जिससे शेयर बाज़ार और विदेशी निवेश पर बड़ा नकारात्मक असर पड़ना तय है।

अभी भी विदेशी निवेशक शेयर बाजार से अपना निवेश निकालकर भाग रहे हैं। सोमवार से गुरुवार तक सरकार और भारत की वित्तीय संस्थाएं शेयर बाजार को संभालने की कोशिश करती हैं। शुक्रवार आते-आते मार्केट टूट कर मुनाफा वसूली करने लगता है। इसमें भारत की वित्तीय संस्थाएं लगातार खोखली होती चली जा रहे हैं। इस स्थिति के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की बनती है। रिजर्व बैंक और आर्थिक नीतियों पर सरकार की दखलंदाजी 2019 के बाद से लगातार बढ़ती जा रही है। रिजर्व बैंक में अब अर्थशास्त्रियों का स्थान प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के उन लोगों ने ले लिया है जो अर्थ का अ, ब, स, द भी नहीं जानते हैं। वर्तमान स्थिति में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को तत्काल ठोस कदम उठाने होंगे। विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना होगा, सरकार को वित्तीय घाटे को नियंत्रित करना होगा। उद्योग एवं निर्यात से जुड़े क्षेत्रों को राहत पैकेज देना होगा। गैर जरूरी आयात और भारत से विदेशी मुद्रा को विदेश जाने से रोकने के लिए पर्यटन और घूमने-फिरने जैसे उपायों पर रोक लगानी होगी। ऐसे उपाय करने होंगे, जो रुपये को स्थिर करने में मदद कर सकते हों। सरकार और रिजर्व बैंक को महंगाई पर नियंत्रण रखने की नीतियां बनानी होंगी। नीति-निर्माण में पारदर्शिता के साथ काम करना होगा। भारत के पास संभावनाएँ बहुत हैं। इसके लिए सरकार को स्वयं अर्थव्यवस्था के सत्य को समझने की जरूरत है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अर्थव्यवस्था को लेकर आम आदमी को भी सही स्थितियां बताए। आर्थिक प्रबंधन के मोर्चे पर जो स्थिति देखने को मिल रही है, यदि इसे समय रहते संभाला नहीं गया, तो यह चूक देश को भारी महँगी पड़ सकती है। आईएफएम की चेतावनी को एक तकनीकी रिपोर्ट मानकर अनदेखा करना इस समय की सबसे बड़ी भूल होगी। अर्थव्यवस्था के बारे में भारत के लिए यह एक स्पष्ट संकेत है। भारतीय अर्थव्यवस्था को त्वरित और निर्णायक सुधारों की जरूरत है। सही समय पर सही कदम न उठाए गए, तो रुपया केवल अस्थिर मुद्रा नहीं, बल्कि आर्थिक जोखिम का बड़ा कारण बन सकता है। सरकार ने पिछले 12 वर्षों में बड़े-बड़े सपने दिखाए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में डॉलर 90 रूपये पार कर चुका है। भारत के आयात और निर्यात में असंतुलन बना हुआ है, जिसके कारण विदेशी मुद्रा कम आ रही है। आयात करने के लिए हमें ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ रही है। सारे उद्योग और व्यापार इस समय वैश्विक कारोबार कर रहे हैं। इसका असर भारत के आम आदमी और भारतीय अर्थ व्यवस्था में पड़ना तय है। अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार को 4 और 5 ट्रिलियन डॉलर के सपने देखने के स्थान पर आंखें खोलकर भारत की अर्थव्यवस्था को देखना होगा। अच्छे अर्थशास्त्रियों की सहायता लेनी होगी। राजनेता और नौकरशाह मिलकर भी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार को लेकर 93 से 96 तक उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक जो कमाया था। भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया था। पिछले 10 से 11 वर्षों में भारत सरकार की गलत नीतियां और ओवर कॉन्फिडेंस ने सब कुछ खतरे में डाल दिया है। समय रहते सरकार को अपनी नीतियों में सुधार करना पड़ेगा। भारत में कारोबार बढे इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। असंगठित क्षेत्र को पुनः जीवित करना पड़ेगा। भारत का असंगठित क्षेत्र सबसे ज्यादा कारोबार करता है। सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। यही भारत की अर्थव्यवस्था की रीड़ की हड्डी है। इस बात को सरकार, उसके नीति निर्धारकों और वित्तीय संस्थानों को समझना होगा। अन्यथा भारत की स्थिति 2008 में जिस तरह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था तबाह हुई थी, भारत भी उसी दिशा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अभी डॉलर 90 के आसपास है, जल्द ही 100 रूपये तक पहुंचने की भविष्यवाणी अर्थशास्त्री करने लगे हैं। इस तथ्य का, सरकार को ध्यान मे रखना होगा। अब आंख बंद करके नहीं बैठा जा सकता है, ना ही नोसिखियों के भरोसे अर्थव्यवस्था को छोडा जा सकता है।

फ़िलीस्तीन की धुन्ध में उगती आशा की किरण

फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस, जो प्रतिवर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 181 के स्मरण में मनाया जाता है। यह फ़िलिस्तीनी अधिकारों और आत्मनिर्णय के लिए चल रहे संघर्ष को रेखांकित करता है, विशेष रूप से गाज़ा में मानवीय संकट के बीच। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, न्याय और फ़िलिस्तीनी राज्य के दर्जे को मान्यता देने का आह्वान करता है। ग़ाज़ा में पिछले वर्षों में हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है, यह इलाक़ा अपने इतिहास के सबसे गम्भीर आर्थिक संकट से गुज़र रहा है, और नाज़ुक युद्धविराम के बावजूद बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है, यहां से आती हुई तस्वीरें देखकर किसी भी संवेदनशील इन्सान का हृदय टूट जाता है, युद्धविराम लागू होने के बाद भी लगभग 67 बच्चों की मौत हो चुकी है द्य गाज़ा में लाखों लोग भीषण भूख और अकाल का सामना कर रहे हैं, और बच्चे गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं द्य

10 अक्टूबर 2025 को युद्धविराम समझौता हुआ, जिससे 20 बंधकों की सुरक्षित वापसी हो सकेगी तथा गाजा में सहायता बढ़ सकेगी। 13 अक्टूबर को, ढ्ढष्टक्रष्ट ने 20 बंधकों को इज़राइली अधिकारियों और 1,808 फ़िलिस्तीनी बंदियों को गाज़ा और पश्चिमी तट तक सुरक्षित पहुँचाया। उस दिन कुल 1,718 बंदियों और 250 कैदियों को रिहा किया गया, और ढ्ढष्टक्रष्ट ने सभी के रिहाई-पूर्व साक्षात्कार आयोजित किए। मृत बंधकों और फ़िलिस्तीनी बंदियों के अवशेषों का स्थानांतरण जारी है।

फिलिस्तीन के लिए यह तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 181 की याद में मनाया जाता है, जिसमें 1947 में फ़िलिस्तीन को अलग-अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया था। यह दिवस 1978 से मनाया जा रहा है और फ़िलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनके अधिकारों के लिए चल रहे संघर्षों को उजागर करता है।

इस वर्ष का स्मरणोत्सव, जो 29 नवंबर, 2025 को आयोजित होगा, गाजा में चल रहे मानवीय संकट के कारण एक अत्यंत मार्मिक समय पर हो रहा है, जो हाल के संघर्षों के कारण और भी बदतर हो गया है। फ़िलिस्तीनियों के लिए सम्मान, अधिकार, न्याय और आत्मनिर्णय के मूल उद्देश्य पहले से कहीं अधिक मायावी प्रतीत होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख ने हमास द्वारा किए गए हमलों और फ़िलिस्तीनियों को दी गई सामूहिक सज़ा, दोनों की निंदा की और तत्काल मानवीय राहत की माँग की। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की ओर से सम्पूर्ण मानवीय सहायता की आवश्यकता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण संदेश सुने गए, विशेष रूप से यूएनआरडब्ल्यूएस की ओर से, जो लाखों फिलिस्तीनियों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करती है।

फ़िलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के प्रयोग संबंधी समिति के अध्यक्ष शेख़ नियांग ने कहा कि पिछले दिनों में गाज़ा में 52,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं और इनमें आधे से ज़्यादा महिलाएँ और बच्चे हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अभूतपूर्व मानवीय आपदा थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने संप्रभु राज्यों की पारस्परिक मान्यता के साथ इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और दुनिया भर के अन्य कार्यालयों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। इनमें विशेष बैठकें शामिल होंगी जहाँ वैश्विक नेता और कई देशों के प्रतिनिधि फ़िलिस्तीनियों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करेंगे और उनके अधिकारों को मान्यता देने का आग्रह करेंगे।

पूर्व में फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी आज जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाज़ा पट्टी और पश्चिमी तट में रहने वाले लगभग 59 लाख पंजीकृत फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों को महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करती है। ह्रक्रङ्ख 663 से ज़्यादा स्कूलों के माध्यम से शिक्षा, 125 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से व्यापक स्वास्थ्य सेवा, और कमज़ोर आबादी के लिए खाद्य सहायता और नकद सहायता जैसी राहत सहायता प्रदान करती है। यह एजेंसी संघर्षों में आपात स्थितियों में आश्रय और आवश्यक वस्तुएँ प्रदान करके भी प्रतिक्रिया देती है। यह अपने द्वारा संचालित 58 मान्यता प्राप्त शरणार्थी शिविरों में अपने बुनियादी ढाँचे में निरंतर सुधार कर रही है। लगभग 30,000 कर्मचारियों, जिनमें से स्वयं फ़िलिस्तीनी शरणार्थी हैं, के साथ यह अल्पकालिक मानवीय आवश्यकताओं और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों, जैसे कि लाखों फ़िलिस्तीनियों को चल रहे संघर्षों और कठिनाइयों के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने, दोनों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बेहद ज़रूरी है कि इस युद्धविराम समझौते का पालन किया जाए। हमें स्थिरता और पुनर्निर्माण के लिए एक स्थायी प्रतिबद्धता देखने की ज़रूरत है, जिसमें सभी पक्ष गाज़ा में नागरिकों, सहायताकर्मियों और चिकित्सा सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जिससे फिलिस्तीन में भी खुशियो की सुबह हो।

दिलीप कुमार पाठक

असली लोकतंत्र का दृश्यः जेसीबी में लटके युवक

सड़क किनारे जो झुग्गियां बना कर रहते हैं, वे देश के नागरिक हैं या नहीं? क्या देश के नागरिक वहीं हैं जो मुफ्त में रोटियां तोड़ते हैं, देश का पैसा लूट कर बहुमंजिली इमारतें बनवाते हैं या सरकार के तलवे चाट कर या चटवा कर अकूत संपत्ति जमा करते हैं। झुग्गियों में रहने वालों की कभी गणना नहीं हुई। गणना होनी चाहिए, जिससे पता तो चले कि देश का विकास कितना हुआ है? दूसरी तरफ सरकार अपने पैसे से जनता की जमीन जबर्दस्ती खरीद लेती है और 1050 एकड़ जमीन महज एक रुपए में तीस वर्षों के लिए दे देती है। नयी सरकार बनते ही बिहार के कई जिलों में जनता सफाई योजना चल रही है। समस्तीपुर, जमुई आदि जिलों में सरकार की यह अमानुषिक कार्रवाई चल रही है। एक जगह मैंने देखा कि जेसीबी से दो युवक लटक गये। वे हवा में तने रहे। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एक जगह एक आदमी कह रहा है कि मैं तो बीजेपी का कट्टर समर्थक हूं, बल्कि मेरा पूरा मुहल्ला बीजेपी मय है। जेसीबी को क्या मालूम कि कौन किसका समर्थक है? आप रहिए समर्थक, लेकिन बीजेपी कभी गरीब - गुरुआ के समर्थक नहीं रही। धन्ना सेठों के यहां पली- बढ़ी और हिन्दू राष्ट्र का सपना दिखाते हुए मुस्लिमों पर बरसते हुए यहां तक आयी है। अब तो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया गया है। बाहुबली फिल्म आने के बाद यह प्रश्न तैरने लगा कि ' कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा' ? उसी तरह से यह पता करना मुश्किल होगा कि झुग्गियां क्यों उजाड़ी जा रही हैं और उजाड़ी जा रही हैं तो उन्हें पहले बसा क्यों नहीं दिया जाता? दरअसल ये लोग सिर्फ घर नहीं बसाते हैं, बल्कि रोजी रोजगार खड़े करते हैं। मैंने अपने शहर में देखा है कि एक दिन पुलिस आती है। माइक लगाकर घोषणा करती है कि अतिक्रमण कारी अपनी दूकानें हटा लें। एक दिन दूकानें हट जाती हैं और दूसरे दिन से फिर दूकानें बसने लगती हैं। देश का जो मध्य वर्ग और उच्च वर्ग है, वह खुद खून पसीना नहीं बहाता। वह बैठ कर खाता है। उल्टे-सीधे काम कर अपना उल्लू सीधा करता है। सरकार के लिए भक्ति गीत लिखता है और कमेरा वर्ग से नफ़रत करता है। जब आप ऐसी नीतियां बनायेंगे, जो गांव- देहात के संसाधनों को लूट कर शहर में जमा होगा। गांव देहात निछट्ट उजाड़ होगा तो जीने के संसाधनों की तलाश में लोग शहर आते हैं। जहां मैं रहता हूं। उसके थोड़ी ही दूर पर जीरो माइल है। सड़क किनारे बंसखोरों ने चार पांच झुग्गियां बना ली हैं। वहां न पानी का इंतजाम है, न ट्वायलेट का- तब भी बाल बच्चों के साथ रहते हैं। धूलों से झुग्गियां पट जाती हैं। तमाम परेशानियां हैं, तब भी वे? परेशान नहीं दिखते। बच्चे हाथ में रोटी या कटोरे में भात लिए खाते रहते हैं। उन्हें शायद ही पता हो कि देश में लोकतंत्र है और संविधान में उसके लिए भी प्रावधान है। दुष्यंत ने लिखा है -' कहां तो तय था चिरागां हरेक घर के लिए, कहां चिराग़ मयस्सर नहीं शहर भर के लिए।' संविधान में एक बड़ी गड़बड़ी है। वह आर्थिक गैर बराबरी के बारे में मौन है।

मानस एवं वाल्मीकि रामायण में श्रीराम और रावण की सेना

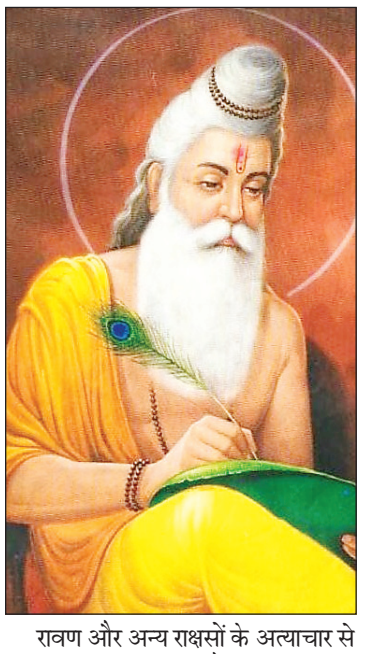

रावण और अन्य राक्षसों के अत्याचार से पृथ्वी, सब देवता, मुनि और गन्धर्व ब्रह्माजी के सत्यलोक गए। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया था। शिवजी भी कहते हैं कि हे पार्वती मैं भी उनके साथ प्रभु को ढूँढ रहे थे कि आकाशवाणी हुई। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों ! डरो मत ! तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देवताओं तुम निर्भय हो जाओ। भगवान की वाणी सुनकर सब देवता तुरन्त लौट गए। उस समय ब्रह्माजी ने पृथ्वी को समझाया।

यहीं से रावण को परास्त करने की योजना एवं रावण के विरुद्ध देवताओं की सेना की तैयारी का श्रीगणेश हुआ।

दोहा- निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहदू सिखाई।

बानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाई।।

श्रीरामचरितमानस बालकाण्ड दो. 197

देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर-धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्माजी अपने लोक चले गए। सभी देवता भी अपने-अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शान्ति मिली। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण किया। उनमें अपार बल और प्रताप था। वे पृथ्वी पर पहुँच कर भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे, बस यहाँ से श्रीराम की सेना की उत्पत्ति हुई।

शिवजी ने उमाजी को इनकी संख्या का जो वर्णन मानस में किया है वह अद्भुत है।

बानर कटक उमा मैं देखा। सो मूरुरव जो करन चह लेखा।।

आइ राम पद नावहिं माथा। निरखि बदनु सब होहि सनाथा।।

श्रीरामचरितमानस किष्किन्धाकाण्ड 22-1

शिवजी कहते हैं कि हे उमा ! वानरों की वह सेना मैंने देखी थी। उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आ-आकर श्रीरामजी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और श्रीमुख दर्शन करके कृतार्थ होते हैं।

वाल्मीकिरामायण में श्रीराम की वानर सेना

शुक तथा सारण नामक गुप्तचर ने रावण को श्रीराम की वानर सेना के बारे में कहा कि राजन जिन्हें आप मतवाले महाराजाओं के समान वहाँ खड़ा देख रहे हैं जो गंगा नदी के तट के वटवृक्षों और हिमालय के शाल वृक्षों के समान जान पड़ते हैं, इनका वेग दुस्सह है। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान हैं। दैत्यों और दानवों के समान शक्तिशाली तथा युद्ध में देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं-

एषां कोटिसहस्राणि नव पञ्च च सप्त च।

तथा शंकु सहस्राणि तथा वृन्दशनि च।।

एते सुग्रीवसचिवारू किष्किन्धानिलयारू सदा।

हरयो देवगन्धर्वैत्पन्नारू कामरुपिणरू।।

वाल्मीकिरामायण युद्धकाण्ड सर्ग 28-5

इनकी संख्या इक्कीस कोटि सहस्र शंकु और सौ वृन्द हैं। (इन संख्याओं की स्पष्ट व्याख्या लेख में नीचे किया गया है।) ये सब के सब वानर सदा किष्किन्धा में रहने वाले और सुग्रीव के मन्त्री हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गन्धर्वों से हुई है। ये सभी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं।

मनीषी पुरुष सौ लाख की संख्या को एक कोटि कहते हैं और सौ सहस्र कोटि एक नील को एक शंकु कहा जाता है। एक लाख शंकु को महाशंख नाम दिया गया है। एक लाख महाशंकु को वृन्द कहते हैं। एक लाख वृन्द का नाम महावृन्द है। एक लाख महावृन्द को पदम कहते हैं। एक लाख पदम को महापदम माना गया है। एक लाख महापद को खर्व कहा जाता है। एक लाख खर्व का महाखर्व होता है। एक सहस्र महाखर्व को समुद्र कहते हैं। एक लाख समुद्र को ओध कहते हैं और एक लाख ओध को महौध संज्ञा दी गई है।

इस प्रकार सहस्र कोटि, सौ शंकु, सहस्र महाशंकु, सौ वृन्द, सहस्र महावृन्द, सौ पदम, सहस्र महापदम, सौ खर्वे, सौ समुद्र, सौ महोघ तथा समुद्र-सदृश सौ कोटि महौध सैनिकों से वीर विभीषण से तथा अपने सचिवों से घिरे हुए वानरराज, सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकारते हुए सामने आ रहे हैं।

महातेजस्वी श्रीरघुनाथजी गरुड़व्यूह का आश्रय ले वानरों के बीच में विराजमान हैं और मुझे विदा करके लंका पर चढ़े चले आ रहे हैं। इसके बाद शार्दूल ने सेना के कतिपय महाशक्तिशाली योद्धाओं के नाम बताए। उस वानर सेना में जाम्बवान नाम से प्रसिद्ध एक वीर है, जिसको युद्ध में परास्त करना बहुत कठिन है। वह ऋक्षरजा तथा गद्गद का पुत्र है। गद्गद का एक दूसरा पुत्र भी है जिसका नाम धूम्र है। इन्द्र के गुरु बृहस्पति का पुत्र केसरी है जिनके पुत्र हनुमान ने अकेले ही यहाँ (लंका में) आकर पहले बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला था। सुषेण धर्म का पुत्र है। दधिमुख नामक सौम्य वानर चन्द्रमा का बेटा है। सुमुख, दुर्मख और वेगदर्शी नामक वानर ये मृत्यु के पुत्र हैं।

निश्चय ही स्वयंभू ब्रह्मा ने मृत्यु की ही इन वानरों के रूप सृष्टि की है। स्वयं सेनापति नील अग्नि का पुत्र है। वीर हनुमान वायु का बेटा है बलवान औश्र दुर्जय वीर अंगद इन्द्र का नाती है। शक्तिशाली वानर मैन्द और द्विविद ये दोनों अश्विनीकुमारों के पुत्र हैं। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गन्धमादन ये पाँच यमराज के पुत्र हैं और काल एवं अन्त के समान पराक्रमी हैं। दशरथ नन्दन श्रीराम ने युवावस्था में अकेले खर-दूषण और त्रिशिरा का संहार किया है। इस भूखण्ड में श्रीरामचन्द्रजी के समान पराक्रमी वीर दूसरा कोई नहीं है।

इन्होंने ही विराध और काल के समान विकराल कबन्ध का भी वध किया है। लक्ष्मणजी भी गजराज के समान पराक्रमी हैं, इनके बाणों का निशाना बन जाने पर देवराज इन्द्र भी जीवित नहीं रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख ये दोनों वानर भगवान सूर्य के और सपुत्र है। हेमकूट नाम का वानर वरुण का पुत्र भी है।

महान वीर नल विश्वकर्मा के पुत्र वेगशाली और पराक्रमी दुर्धर वसु देवता के पुत्र है।

रावण की सेना में राक्षसों की संख्या

गजानां दशसाहस्रं रथानामयुतं तथा।

ह्यानामयुते द्वे च साग्रकोटिश्च रक्षसाम।।

वाल्मीकिरामायण युद्धकाण्ड सर्ग 37-16

रावण को सेना में दस हजार हाथी, दस हजार रथ, बीस हजार घोड़े और एक करोड़ से ज्यादा पैदल राक्षस थे।

इतना सब होने पर भी श्रीरामजी के समक्ष महायुद्ध में रावण का अहंकार होने के कारण श्रीराम द्वारा वध हुआ।

डॉ. नरेन्द्रकुमार मेहता

नीतीश कैबिनेट के नए फैसलों से उभरती संभावनाएँ

बिहार सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनसे राज्य के आर्थिक, औद्योगिक, तकनीकी और सामाजिक परिदृश्य में व्यापक बदलाव आने की उम्मीद है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लिए गए इन निर्णयों में एक करोड़ नौकरियाँ व रोजगार, डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, पुरानी बंद पड़ी मिलों का पुनरुद्धार, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस मिशन की शुरुआत, और पर्यावरण-सम्मत आधुनिक टाउनशिपों का विकास जैसे बड़े कदम शामिल हैं।

यह केवल योजनाओं का विस्तार नहीं, बल्कि बिहार को एक उद्योग प्रधान तकनीक संचालित और रोजगार-समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करने का एक बड़ा रोडमैप है। बिहार में विकास की नई लहर की एक पृष्ठभूमि की सक्रियता देखने को मिल रही है।बिहार लंबे समय तक आर्थिक पिछड़ेपन, उद्योगों के पलायन और कम रोजगार अवसरों जैसी चुनौतियों से जूझता रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढाँचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क नेटवर्क में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन उद्योग और टेक्नोलॉजी आधारित विकास अभी भी अपेक्षा से कम था।नीतीश कैबिनेट के हालिया फैसलों ने उस खालीपन को भरने का प्रयास किया है, जिससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि बिहार के युवाओं को यहाँ ही रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे।एक करोड़ नौकरियाँ एवं रोजगार की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है। बिहार युवाओं के लिए बड़ी उम्मीदलेकर आया है।सरकार ने अगले कुछ वर्षों में एक करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह निर्णय बिहार के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा रोजगार मिशन माना जा रहा है। इस योजना में सरकारी भर्तियाँ,शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्ती,स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टर, नर्स और टेक्नीशियन की नियुक्ति,पुलिस बल में रिक्तियों की पूर्ति और पंचायती राज और शहरी निकायों में नियुक्तियाँ शामिल है। निजी क्षेत्र में रोजगार भी उपलब्ध होगा।यहाँ डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, बंद मिलों को चालू करने और समर्थन मूल्य को

बढ़ावा देने जैसी योजनाएँ सीधे नए रोजगार पैदा करेंगी। कौशल-आधारित रोजगार पर भी पूरा फोकस है।

सरकार उद्योगों की जरूरतों के अनुसार नए कोर्स और ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू करेगी।बिहार से होने वाले बड़े पैमाने पर पलायन में कमी आएगी।युवावर्ग गुजरात,मुम्बई आदि औधोगिक शहर की तरफ पलायन कर रहे है।इस दिशा में जरुर कमी आएगी। इसके साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूती देखने को मिलेगी।युवाओं में उभरता आत्मविश्वास इस बात का धोतक है कि युवाओं ने उस सिस्टम पर भरोसा किया है,जिसकी कथनी करनी समान है।बिहार में चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने की दिशा में सदन में चर्चा हुई।बिहार कभी चीनी उद्योग के लिए देशभर में प्रसिद्ध था, लेकिन बदहाल प्रबंधन, तकनीकी पिछड़ापन और बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश चीनी मिलें बंद हो गईं।

कैबिनेट का नया निर्णय है किपुरानी चीनी मिलों को आधुनिक तकनीक से पुनः शुरू किया जाएगा।

गन्ना किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और डिजिटल भुगतान की सुविधाएं उपलब्ध होगी।एथेनॉल उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि एथेनॉल नीति बिहार के लिए लाभदायक है।संभावित लाभ पर सभी की नजर है।हजारों स्थायी रोजगार,कृषि-केंद्रित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।एथेनॉल उत्पादन के माध्यम से राज्य की अतिरिक्त आय बढ़ेगी।डिफेंस कॉरिडोर उद्योग और सुरक्षा का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है।

बिहार में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम है। रक्षा उत्पादन क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में बिहार के लिए यह अवसर बड़ी छलांग साबित हो सकता है।डिफेंस कॉरिडोर से फायदेभी अपार है।ड्रोन, हथियार, गोला-बारूद, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण उच्च तकनीकी कौशल की मांग और विदेशी व घरेलू कंपनियों का निवेश आदि सम्मिलित होगा।युवाओं के लिए उच्च वेतन वाली नौकरियाँ और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई चेन उद्योगों का विकास आदि नई सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है।यह कॉरिडोर बिहार को देश के रणनीतिक औद्योगिक नक्शे पर एक नई जगह देगा।

सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क डिजिटल बिहार की आधारशिला है।आज दुनिया चिप और सेमीकंडक्टर की कमी से जूझ रही है। भारत भी वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर जोर दे रहा है। बिहार ने इस दौड़ में शामिल होकर यह संकेत दिया है कि राज्य डिजिटल अर्थव्यवस्था में योगदान देने को तैयार है।चिप डिजाइन व टेस्टिंग लैब इस पार्क में उपलब्ध होंगे।वेफर फैब्रिकेशन यूनिट,इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्माण,अनुसंधान केंद्रस्थापित होंगे।

अत्याधुनिक तकनीकी नौकरिया उच्च निवेश इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का प्रसार सहित लाभ उपलब्ध होगा। नीतीश सरकार ने पुरानी बंद मिलों का पुनरुद्धार और औद्योगिक धरोहर को नई जान देने के लिए मार्ग प्रशस्त किये है।बिहार की कई चीनी मिलें, जूट मिलें, कपड़ा मिलें और कृषि आधारित उद्योग दशकों से बंद पड़े हैं।सरकार ने निर्णय लिया है किपब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जाएगा।नई तकनीकों से मिलों को आधुनिक रूप दिया जाएगा।

स्थानीय स्तर पर समर्थन मूल्य को जोड़कर सप्लाई चेन तैयार होगी।इससे स्थानीय रोजगार सृजन,किसानों को स्थिर बाजार औरग्रामीण औद्योगिकीकरण की गति बढ़ेगी।आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस मिशन की स्थापना से टेक्नोलॉजी का नया युग आरम्भ होगा।दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित तकनीकों की ओर बढ़ रही है। बिहार सरकार का आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस मिशन इन उभरते क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित करने और शोध को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस मिशन के प्रमुख उद्देश्य यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित स्टार्टअप्स का विकास होगा।सरकार की सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि युवाओं के लिए आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के कोर्स,आईटी इंडस्ट्री को बिहार में बढ़ावा आदि फायदे उपलब्ध होंगे।यह पहल बिहार को तकनीकी क्रांति में अग्रणी बनाएगी।नियोजि,पर्यावरण-संगत और आधुनिक टाउनशिप की आवश्यकता पर जोर दिया है।

बिहार की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। शहरों पर बोझ बढ़ रहा है। अव्यवस्थित बसावट, ट्रैफिक, प्रदूषण और बुनियादी सुविधाओं की कमी एक बड़ी चुनौती है।

शांति हेतु भगवान राम का ध्यान जरुरी

मन बहुत चंचल होता है वो समय से भी तेज गति से भ्रमण करता है और मन कब अशांति की ओर जाता है जब आप किसी की बातों या अपने गलत काम करने से डर पैदा होता है भगवान राम का नाम ही पूर्ण ब्रह्माण्ड में बहुत तेजी से सकारात्मक ऊर्जा की तरह बहता है उसे पकड़ने की जरुरत है हम जब उनका ध्यान करते हैं तो मन शांत होता है और दया का भाव उत्पन्न होता है सभी धर्मों में मानवता ही सच्ची सेवा को उपदेश देती है इसलिए पहली बात तो यह है कि भगवान राम एक विचार है जिसे किसी भी धर्म से अलग थलग करना आपकी भूल है क्योंकि वो एक विचारों पर टीका है जिसमें सत्य न्याय अहिंसा और मानवता का संदेश देती है अतः जब ध्यान करेंगे तो भगवान राम की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है जिससे मन में उठ रहे गलत विचारों का धीरे धीरे निकलने लगता है कुछ लोग पूछते हैं क्या ध्यान करेंगे लेकिन पहले कोशिश कर के देखिए कुछ समय के लिए मौन व्रत धारण कर ले और अपने अंदर आ रहे सभी गलत विचार को भगवान राम को सौंप दें और पूरे तनमन धन से भजन सुने उसके बाद आपका प्रेम भगवान राम के प्रति ऐसा उमड़ पड़ेगा की आप आपको उनके बिना मन व्याकुल हो जायेगा और क़ोई भी ताकत उससे अलग नहीं कर सकती है जैसे पानी के अंदर मछली रहती है और जो मछुआरा के पैर के पास रहती है वो उस जाल में नहीं फंसती और बच जाती है खैर मछली तो मछली है अगर जाल में फंस भी गई तो पानी के बिना दम तोड़ देगी अतः यदि मछली पानी के बिना नहीं रह सकती वैसे ही राम का भक्त भगवान राम के भवसागर में एक बार चली गई तो बापस आना नामुमकिन है क्योंकि शरीर राम के बिना नष्ट हो सकता लेकिन आत्मा नहीं और शरीर का नष्ट होना एक न एक दिन निश्चित है तो उस परमात्मा का ध्यान जरुरी है जो भावसागर पार करा सकता है राम का शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। इसका आभास आपको मन में भगवान राम का ध्यान करने से होगा रामायण में कहा गया है तिनके हृदय बसहु रघुराया॥ अर्थ - इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति पर भगवान श्रीराम की कृपा होती है, उसके जीवन में कोई भी दुख ज्यादा देर टिक नहीं सकता। तुलसी दास को राम नाम सुनना, बोलना और स्मरण करना श्रीराम और लक्ष्मण के समान ही प्यारा है। राम नाम का वर्णन करने में अर्थ और फल में भिन्नता जान पड़ती है, लेकिन यह जीव और ब्रह्म को समान भाव से सदैव एक रूप-रस में रखने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के एक चौपाई में कहते हैं

को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि गुन भेदु समुझिहहिं साधूादेखिअहिं रूप नाम आधीना। रूप ग्यान नहिं नाम बिहीना॥

जिसका अर्थ है इनमें से किसी को छोटा या बड़ा कहना अपराध है, इनके गुणों का भेद साधु पुरुषों से सुनकर ही समझ में आ सकता है। रूप को नाम के अधीन होकर ही देखा जा सकता है, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है इसलिए भगवान राम का ध्यान कर ही उनके नाम की महिमा को समझी जा सकती यें जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है विपरीत परिस्थिति में संयम से काम लें भगवान राम आपकी नइया पार लगा देंगे। एक और चौपाई में तुलसीहै दास जी कहते हैं राम नाम के दोनों अक्षर अत्यन्त मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्रों के समान हैं। राम नाम सभी भक्तों को स्मरण करने में आसान और सुख को प्रदान करने वाला है, जो इस लोक में सुख देने के साथ-साथ भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति भी कराता है।

सराफा चौपाटी को लेकर नहीं थम रहा विवाद, दुकानदारों के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने भी निगम पर साधा निशाना

चौकसे ने कहा 80 दुकानों की जो सूची बनी वह राजनैतिक लोगों के साथ साथ सांठगांठ की सूची है, बिना किसी को हटाए पूरी चौपाटी गांधी हॉल प्रांगण में शिफ्ट की जा सकती है ...

इन्दौर । पिछले तीन दिनों से सराफा चौपाटी की दुकानों को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर चौपाटी से बाहर किए गए कई दुकानदार तमाम आरोप लगा रहे हैं तो वहीं निगम अफसर भी सूची में शामिल दुकानदारों के मामले में पडताल कर रहे हैं। वहां से हटाए गए दुकानदार कोर्ट से स्टे न ले आएं इसके लिए निगम ने हाईकोर्ट में केविएट दायर की है। वहीं दूसरी ओर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिन्टू चौकसे ने चौपाटी के नाम पर कई दुकानदारों को हटाए जाने पर कहा कि सूची ही गड़बड़ और वह सांठगांठ की सूची लगती है। पूरी चौपाटी को गांधी में शिफ्ट किया जा सकता है ताकि सराफा चौपाटी के आसपास रहने वाले परिवार भी परेशानी से बच सके।

दो दिन पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव से मिलने पहुंचे सराफा चौपाटी के कई दुकानदारों ने सूची में शामिल 80 दुकानों को लेकर तमाम आरोप लगाए थे और कहा था कि इनमें कई दुकानें एक ही परिवार की हैं और साथ ही एक ही परिवार को 3-4 दुकानें लगाने की अनुमति दी गई। इस पर महापौर ने सूची की दोबारा जांच कराने को कहा था और उस आधार पर अब नगर निगम की टीम सूची में शामिल दुकानों की पड़ताल कर रही है। कौनसी दुकान कब से किस व्यंजन की लगाई जा रही है और इसके साथ साथ कुछ अन्य वेकल्पिक स्थान भी ढूंडे जा रहे हैं जहां सराफा से हटाए गए दुकानदारों को जगह दी जा सके। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक कुछ स्थान निगम के अधिकारियों ने शनिवार को देखें हैं और उस पर आला अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। वहीं नगर निगम ने हटाए गए व्यापारियों द्वारा कोर्ट से स्टे ले आने की आशंका के चलते हाईकोर्ट में निगम की ओर से केविएट दायर कर दी है। इस पूरे मामले में शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिन्टू चौकसे ने भी मोर्चा संभालते हुए कहा है कि सराफा चौपाटी को लेकर बनाई गई सूची दुकानदारों की सूची नहीं सांठगांठ की सूची नजर आती है। यह सूची राजनैतिक लोगों की है। उन्होंने कहा कि हरदा विस्फोट के बाद आनन फानन में नगर निगम ने सराफा चौपाटी को लेकर कमेटी बनाई और चाईनिज़ व्यंजनों और कुछ अन्य नए व्यंजनों को लेकर कई दुकानदारों को बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि गांधी हॉल एक ऐसा स्थान है जहां पर सराफा चौपाटी शिफ्ट की जा सकती है और इसके लिए किसी भी दुकानदार को चौपाटी से हटाना ही नहीं पड़ेगा। इससे चौपाटी के आसपास रहने वाले कई परिवारों को भी राहत मिलेगी क्योंकि कई बार उन्हें मेडिकल एमरजेंसी के दौरान रात में चौपाटी लगने के दौरान तमाम मशक्कत करनी पड़ती है।

पुरानी 135 बसों के परमिट निरस्त

इंदौर । इन्दौर संभाग के अन्तर्गत स्टेज कैरिज परमिट पर आच्छादित 135 यात्री बसें 15 वर्ष से अधिक पुरानी पाई गई थी जिनके स्थाई परमिट वैध है। ऐसी संभावना थी की उक्त बसें विभिन्न मार्गों पर संचालित हो रही होगी। वाहन स्वामियों/परमिट धारकों को इस शर्त के अधीन परमिट स्वीकृत किया गया था कि परमिट पर किसी भी समय 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का संचालन नहीं किया जायेगा। वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर एवं सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर उक्त स्थाई परमिटों पर अद्यतन मॉडल की वाहन प्रतिस्थापन कराने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु वाहन स्वामियों द्वारा समयावधि में अद्यतन मॉडल की वाहने प्रतिस्थापन नहीं कराई गई।

संभागायुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार इन्दौर संभाग इन्दौर डॉ. सुदाम खाडे द्वारा उक्त 135 यात्री बसों में से 73 यात्री बसों को जारी स्थाई परमिट निरस्त किये गये है शेष 62 यात्री बसों के परमिट निरस्ती की कार्यवाही प्रचलन में है जो आगामी कार्यालयीन दिवस में निरस्त किये जायेगें। उक्त कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी। सचिव मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग श्री मनीष सिंह द्वारा भी इस सबंध में निर्देश जारी किये गये कि स्टेज कैरिज परमिटों पर 15 वर्ष से अधिक पुरानी यात्री बसों का संचालन नहीं किया जायेगा। कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा बस ऑपरेटरों की बैठक आयोजित कर स्टेज कैरिज परमिट पर 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहनों का संचालन न किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया।

चायनीज धागे के इस्तेमाल भंडारण तथा विक्रय प्रतिबंधित

इंदौर (दस्तक)। जिले में मानव जीवन एवं पशु, पक्षियों की सुरक्षा को देखते हुए चायना के धागे के पतंगबाजी में उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही इसका भंडारण तथा विक्रय भी प्रतिबंधित किया गया है।

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। मीडिया व अन्य जनसामान्य द्वारा यह तथ्य ध्यान में लाया गया है कि पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायना के धागे के उपयोग से पक्षियों व जनसामान्य को हानि पहुंच रही है।

कई बार चायना के धागे से पतंग उड़ाते समय पक्षी इसमें उलझ कर फस जाते है और घायल हो जाते है। कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड़ पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते है। चायना धागे की मजबूती इन हादसों का कारण है व इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। निकट भविष्य में मकर संक्रान्ति पर्व आने वाला है तथा इस त्यौहार पर बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है । इस प्रकार चायना के धागे का पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इसके उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

एस आई आर प्रोजेक्ट, निर्णायक साबित हो सकती है हेल्प डेस्क

बीएलओ को शोकाज नोटिस देने के बाद अन्य में घबराहट

इंदौर । मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण प्रोजेक्ट को लेकर जहां अफरा तफरी का माहौल है वहीं इंदौर जिले के इस प्रोजेक्ट में बिछड़ने के बाद अधिकारियों ने ताबड़तोड़ तमाम व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जिसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आने लगे हैं और एस आई आर प्रोजेक्ट के पूरा होने के प्रतिशत में आंशिक वृद्धि भी दर्ज हुई है तो गति भी देखने को मिल रही है वहीं हेल्प डेस्क बनाने का निर्णय भी फिलहाल निर्णायक साबित होता प्रतीत हो रहा है लेकिन 17 बीएलओ को शो काज नोटिस दिए जाने के बाद तमाम बीएल ओ और बीएलओ सहायकों में घबराहट है। इधर छुट्टी रद्द हो जाने के कारण यह तमाम कर्मचारी अधिकारी परेशान हैं जहां की उन्हें परिवार के ही मांगलिक कार्य में सम्मिलित होना है।

जैसा कि सभी जानते हैं देश के 12 राज्यों में एस आई आर प्रोजेक्ट संचालित हो रहा है। गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में मध्य प्रदेश में भी लगभग चार लाख कर्मचारियों का अमला लगा हुआ है हालांकि 6 बीएलओ की मौत के कारण मध्य प्रदेश भी राष्ट्रीय स्तर पर एस आई आर प्रोजेक्ट को लेकर चर्चाओं में है।

इधर मालवांचल में इंदौर की स्थिति कमजोर होने के कारण यहां फिर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अधिकारियों को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के कोप भाजन का भी कहीं न कहीं शिकार बनना पड़ा ।यही कारण है कि इसमें दो दिनों में काफी बदलाव किया गया और एस आई आर प्रोजेक्ट के कार्य के प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर सो हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। इसमें ज्यादातर शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को ही लिया गया है । सो हेल्प डेस्क बनाने के थोड़े अपेक्षित परिणाम मिलने लगे हैं। सूत्रों कहना है की खास तौर पर ऐसे लोग जो की फॉर्म नहीं भर पा रहे थे उनके फार्म भरने की व्यवस्था हो जाने से जिस कारण से कार्य विलंबित हो रहा था उसमें अब सुधार हो गया है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति में सुधार हो जाएगा।

इधर 17 बीएलओ को शो काज नोटिस दिये गये है और अन्य बीएल ओ के कामकाज की भी समीक्षा की जा रही है। क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे बिल हुए हैं जिनका कार्य लक्ष्य से दूर है वहीं उनकी कार्यशैली भी विसंगति पूर्ण है। ऐसे बीएलओ भी कामकाज को लेकर जिला प्रशासन के राडार पर हैं।

सूत्र कहना है कि इधर तमाम ब्लू और उनके सहायकों को उनके नोडल अधिकारियों के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि आज रविवार है और ज्यादातर लोग घरों पर ही मिलेंगे ।छुट्टी होने के चलते आप रविवार को जरा मैदान पकड़कर काम करें। नोटिस के बाद घबराहट सूत्रों कहना है कि वैसे डेढ़ दर्जन बीएलओ को शोकाज नोटिस जारी होने के बाद तमाम बीएलओ और उनके सहायकों मैं घबराहट है ।

एसआईआर का 80 प्रतिशत काम पुरा : कलेक्टर

इंदौर जिले में SIR का काम काफी तेजी से किया जा रहा है कलेक्टर शिवम् वर्मा खुद पूरे काम पर लगातार नजर बनाए हुए है, शनिवार और रविवार की छुट्टी होने के बाद भी सभी बीएलओ मैदान में डटे हुए है और मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम को पूरा कर रहे है कलेक्टर शिवम् वर्मा ने बताया की SIR के काम के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गयी डेडलाइन बेहद करीब है ऐसे में जिला प्रशासन ने अपना 80 प्रतिशत काम लगभग पूरा कर लिया है,साथ ही शहर के 200 बीएलओ ने अपने काम को 100 प्रतिशत पूरा किया है अब पूरे जिले में महज 20 प्रतिशत बचे काम को पूरा करने पर फोकस किया जा रहा है..कलेक्टर शिवम वर्मा ने दावा किया है की 4 दिसंबर के पहले जिले में SIR का काम पूरा कर लिया जाएगा..उम्मीद है की अब इंदौर जिला इस काम में भी प्रदेश में नंबर वन का मुकाम हासिल करेगा।

भाजपा अध्यक्ष की घोषणा जल्द! खरमास के बाद तेज होगी प्रक्रिया, दो नाम सबसे आगे

● नई दिल्ली।

भाजपा को जल्द मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। जे.पी.नड्डा के कार्यकाल विस्तार के बीच, उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान के नाम रेस में सबसे आगे हैं। बिहार में एनडीए की सफलता के बाद एक कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व की अटकलें भी हैं। आरएसएस के साथ विचार-विमर्श जारी है, और जनवरी 2026 तक चुनाव संपन्न होने की उम्मीद है।

इस बीच, भगवा हलकों में मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा, जो वर्तमान में सेवा विस्तार पर हैं, के उत्तराधिकारी के रूप में तीन नाम चर्चा में हैं। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने शुक्रवार को बताया, उत्तर प्रदेश के

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और शिवराज सिंह चौहान उन प्रमुख नामों में शामिल हैं जिन पर चर्चा हो रही है। इनमें से, आरएसएस और अमित शाह, दोनों के करीबी माने जाने वाले मौर्य और बिहार चुनाव अभियान के दौरान चुनाव प्रभारी रहे प्रधान, सबसे प्रमुख दावेदारों में उभरे हैं।

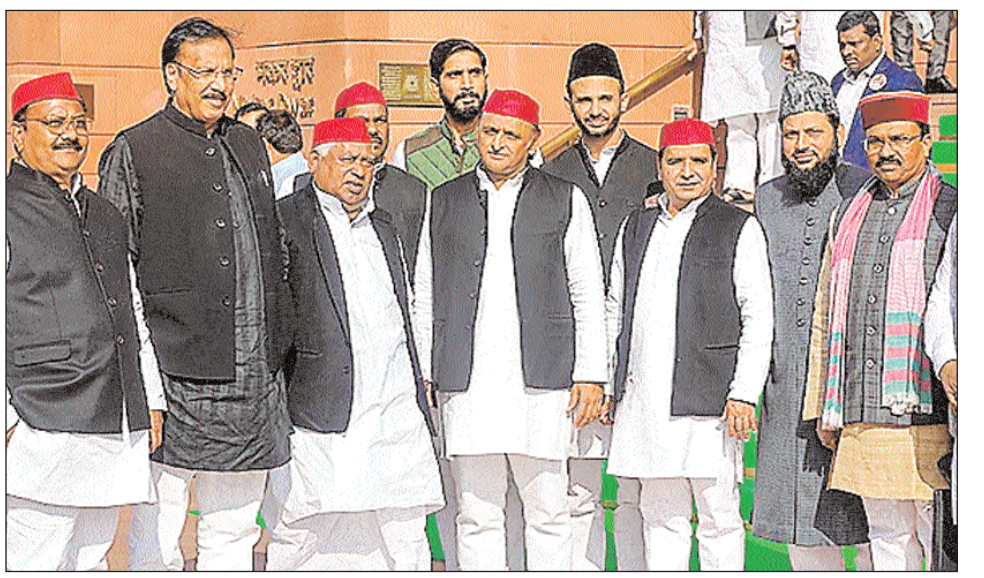

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शीतकालीन सत्र में संसद के बाहर पार्टी नेताओं के साथ।

सावधान : गोलगप्पा मुंह में डालते ही लॉक हो गया महिला का जबड़ा, खुला रह गया मुंह

औरैया। यूपी के औरैया जिले से एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक महिला को गोलगप्पा (पानी पुरी) खाने का शौक महंगा पड़ गया। एक बड़ा गोलगप्पा खाने की कोशिश में महिला का जबड़ा अपनी जगह से खिसक गया, जिसके बाद उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। जिला अस्पताल में इलाज न हो पाने के कारण उसे सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी रेफर किया गया है।

घटना औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र की है। गौरीकिशनपुर ककोर की रहने वाली इंककला देवी (50) अपने परिवार के साथ अपनी भतीजा-बहू की डिलीवरी के लिए औरैया जिला अस्पताल आई थीं। रविवार की सुबह बच्चों की जिद पर पूरा परिवार अस्पताल के पास ही गोलगप्पे के ठेले पर पहुंच गया। जैसे ही इंककला देवी ने एक बड़ा सा गोलगप्पा खाने के लिए अपना पूरा मुंह खोला, उनका जबड़ा अचानक लॉक हो गया। गोलगप्पा आधा अंदर और आधा बाहर रह गया। उन्होंने मुंह बंद करने की लाख कोशिशें कीं, लेकिन जबड़ा अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था।

धर्मशाला में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र और अन्य लोग नशा-विरोधी वॉकथॉन में भाग लेते हुए।

चंडीगढ़ में नहीं बनेगी अलग विधानसभा

● चंडीगढ़।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा सरकार की चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन बनाने की मांग को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को साफ सलाह दी है कि इस मामले में अब चंडीगढ़ प्रशासन से किसी तरह की आगे की कार्रवाई न करें।

केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को स्वतंत्र यूनियन टेरेटरी का ऐलान करने के लिए 131वें शोध बिल को वापस लेने के बाद पंजाब के लिए यह दूसरा बड़ा फैसला लिया है। यह मुद्दा तब चर्चा में आया था जब जुलाई 2022 में जयपुर में हुई उत्तरी जोनल काउंसिल की बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा को नई विधानसभा के लिए भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसके बाद जुलाई 2023 में यूनियन टेरेटरी प्रशासन ने 10 एकड़ जमीन हरियाणा को देने पर सहमति जताई थी। यह जमीन चंडीगढ़ के आईटी पार्क के पास रेलवे लाइट पॉइंट के नजदीक है और इसकी कीमत करीब 640 करोड़ रुपए आंकी गई।

योजना के तहत हरियाणा ने बदले में पंचकूला के सेक्टोरियल क्षेत्र के पास 12 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जनवरी 2024 में यूनियन टेरेटरी प्रशासन ने विस्तृत सर्वे के बाद इसे खारिज कर दिया। शहरी नियोजन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यह जमीन नीची थी, बीच से नाला गुजरता था और कनेक्टिविटी भी उचित नहीं थी। इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुपयुक्त बताया गया।

शेख हसीना को 25 साल की सजा

● ढाका।

बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना को जमीन कब्जाने के मामले में कुल 26 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। ढाका की विशेष अदालत ने सोमवार को पुरबाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में प्लॉट आवंटन में गड़बड़ी मामले में 5 साल की सजा सुनाई।

बांग्लादेश के एंटी-करप्शन कमीशन ने जनवरी में इस मामले में हसीना के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए थे। यह चौथा मामला है, जिसमें हसीना को सजा सुनाई गई है। इससे पहले शेख हसीना को 3 मामलों में 21 साल जेल की सुनाई जा चुकी है।

भांजी और छोटी बहन को भी जेल

हसीना के अलावा उनकी छोटी बहन शेख रेहाना को 7 साल की सजा हुई। वहीं, शेख हसीना की भांजी (ब्रिटेन की सांसद रह चुकी) ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीक को 2 साल की कैद की सजा मिली है। फिलहाल तीनों दोषी बांग्लादेश से फरार हैं। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को तख्तापलट के बाद इस्तीफा देकर भारत आ गईं थी।

ट्यूलिप और शेख रेहाना पर 1 लाख टका का जुर्माना भी लगाया गया है। इसे न चुकाने पर उन्हें 6 महीने की जेल एक्स्ट्रा जेल हो सकती है। मामले के अन्य 14 आरोपियों को 5-5 साल की सजा दी गई है। यह फैसला ढाका के स्पेशल कोर्ट-4 के जज मोहम्मद रबीउल आलम ने सुबह 11 बजे सुनाया। शेख हसीना को 27 नवंबर को पुरबाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट से जुड़े दो मामलों में सजा मिलना अभी बाकी है।

दरैया, सीरिया। दमिश्क के बाहरी इलाके में स्थित एक उपनगर के इस हवाई दृश्य में वर्षों के संघर्ष के बाद तबाह हुई इमारतें खंडर में तब्दिल हो गई है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक अभिषेक साहू द्वारा राजा आफसेट 863/9 नेहरु नगर इंदौर से मुद्रित एवं युग प्रभात कार्यालय 10 प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित,सम्पादक अभिषेक साहू
मो. नं. 9920999817, भारत सरकार समाचार पत्र पंजीयन संख्या - 38189/72, डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/58/2024-2026 Yugindore@gmail.com